उत्तराखण्ड शासन

ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल

उत्तराखंड के ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति पर अंतरिम रिपोर्ट

अप्रैल २०१८

संदेश

देवभूमि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जंगलो, बर्फीले पहाड़ो, नदियों, राज्य में स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और पिरान कलियार के धार्मिक स्थानों के साथ सभी धर्मों के तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में जाना जाता है।

राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग ७०% ग्रामीण इलाकों में रहता है और अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर काफी हद तक निर्भर है। पहाड़ी क्षेत्रों में, ८२% से अधिक आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जिनमें से कई दूरस्थ और दुर्गम हैं।

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों मे लोगों के पलायन की समस्या को हल करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है; जिसे ग्रामीण विकास, पर्यटन की मजबूती, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में निवेश, कृषि, बागवानी, फूलों की खेती आदि पर अधिक जोर देने के माध्यम से हल किया जा सकता है।

ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने और पलायन की चुनौती से निपटने के उद्देश्य से, सरकार ने पिछले साल अगस्त में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया है।

आयोग, जिसका कार्यालय पौड़ी में है; ने ग्रामीण पलायन और संबंधित सामाजिक–आर्थिक मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर इस अंतरिम रिपोर्ट को तैयार किया है। यह रिपोर्ट राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित विकास के लिए राज्य सरकार को मूल्यवान जानकारियां देगी और आयोग को ग्राम्य विकास एवं पलायन पर अपना काम आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

३० अप्रैल २०१८

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री, उत्तराखंड एवं अध्यक्ष
ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग

प्रस्तावना

पलायन किसी व्यक्ति के निवास स्थान पर स्थायी या अर्ध–स्थायी परिवर्तन का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है; हालांकि बहुत कम अवधि के परिवर्तन या उसी क्षेत्र में निवास परिवर्तन को पलायन नहीं माना जाता है। अधिकांश विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन हो रहा है; और अक्सर इन देशों के लोग बेहतर जीवन की तलाश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में भी पलायन करते हैं। उत्तराखंड राज्य पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है; और उसकी अधिकांश आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती हैं। राज्य का भूगोल काफी हद तक पहाड़ी है। चिंता का एक प्रमुख कारण ग्रामीण से अर्द्ध शहरी या शहरी क्षेत्रों में अर्द्ध स्थायी या स्थायी आधार पर लोगों का पलायन है; क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप गांवों की जनसँख्या में गिरावट आई है; जो कई गांवों में दो अंकों में पहुंच गयी है; और इसने प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) को भी घटाया है। दूसरी तरफ, शहरी क्षेत्रों में लोगों का प्रवास, राज्य के भीतर और बाहर दोनों संसाधनों पर तनाव पैदा कर रहा हैं। पहले से ही शहरीकरण की समस्या से जूझ रहे कस्बों और शहरों में पानी की कमी, भीड़भाड़, स्वच्छता और शहरी प्रदूषण से समस्या और भी गंभीर हो रही है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की समस्या आर्थिक असमानताओं के साथ साथ कई अन्य चुनौतियां भी प्रकट कर रही है, जिसमे कृषि में गिरावट, गिरती ग्रामीण आय और एक तनावग्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रमुख है। अतः राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की जानकारी एवं गंभीरता का आंकलन करने हेतु; उत्तराखंड में पलायन की समस्या के समाधान, रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलो में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के गठन को सुनिश्चित किया। इस आयोग के कार्यो में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टीकोण विकसित कर पलायन की गंभीरता को कम करना एवं ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करना, जमीनी स्तर पर बहु–क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार को सलाह प्रदान करना जो जिला और राज्य स्तर पर सयुंक रूप से हो, राज्य की आबादी के उन वर्गों के लिए जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है; हेतु लघु/मध्यम/दीर्घ अवधि की कार्य योजनाओं की सिफारिशें प्रस्तुत करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रित पहल की सिफारिशें और निगरानी करना जो ग्रामीण क्षेत्रों के चौमुखी विकास में सहायक होकर पलायन को रोकने में सक्षम हो प्रमुख है।

आयोग जिसका कार्यालय पौड़ी में स्थित है और अध्यक्षता राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है अक्टूबर २०१७ में काम करना शुरू कर दिया है। आयोग के दल ने राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा किया और ग्रामीण समुदायों के साथ संवाद स्थापित किया विभिन्न विभागों के जिला/खंड और राज्य स्तरीय अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनो, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, छात्रों आदि से पलायन और संबंधित मामलों से जुडी जमीनी स्तर की वास्तविकता एवं स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया। चूंकि, २०११ की जनगणना के बाद पलायन पर राज्यव्यापी तथ्य एवं आंकड़ो की कमी थी इसलिए आयोग ने राज्य के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों का व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया और ग्राम पंचायतों से पलायन के विभिन्न पहलुओं पर प्राप्त तथ्यों एवं आंकड़ो का आकलन और संकलन किया। यह अंतरिम रिपोर्ट राज्य में सामाजिक–आर्थिक

स्थिति और मौजूदा पलायन से संबंधित आंकड़ो को प्रस्तुत करती हैं। इस रिपोर्ट में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के माध्यम से पूरे राज्य में किए गए सर्वेक्षण से पलायन से संबंधित आंकड़ो का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह राज्य में ग्रामीण पलायन की वर्तमान स्थिति की दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

सर्वेक्षण के लिए ग्राम विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) और भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से प्रश्नावली रूप रेखित की गई थी। एफएसआई के सांख्यिकीय विभाग ने प्राप्त तथ्यों एवं आंकड़ो के विश्लेषण के लिए मूल्यवान मार्ग दर्शन प्रदान किया। उनकी सहायता को कृतज्ञता से स्वीकार किया जाता है। आयोग कृतज्ञता के साथ राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्ज करता है।

आयोग माननीय मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों, मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, विशेष रूप से डॉ. मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव ग्राम विकास एवं सदस्य सचिव आयोग, डॉ. राजेंद्र डोभाल, महानिदेशक, यूकोस्ट एवं डॉ. आर. एस. पोखरिया, अपर आयुक्त ग्राम विकास को उनकी सहायता और मूल्यवान सुझावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है।

३० अप्रैल २०१८

डॉ. शरद सिंह नेगी
उपाध्यक्ष

अध्याय ०१

पृष्ठभूमि

उत्तराखंड में ग्रामीण से शहरी इलाकों में पलायन एक बड़ी चुनौती है। २००१ और २०११ की जनगणना के आंकड़ों के मुकाबले राज्य के अधिकांश पहाड़ी जिलों में आबादी की वृद्धि की गति धीमी है। अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जिले की आबादी में १७८६८ व्यक्तियों की २००१ और २०११ के बीच निरंतर गिरावट राज्य के कई पहाड़ी इलाकों से लोगों के पलायन की ओर इशारा करता है। उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों के निवासियों का पलायन होना गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं में है। पलायन की गति इतनी गंभीर है कि कई गांव आबादी के आंकड़ो में एक अंकों में पहुंच गए हैं। आंकड़े यह भी दर्शाते है की देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे जिलों में आबादी की वृद्धि औसत दर से ऊपर है, जबकि यह पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में नकारात्मक है और टिहरी, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में औसत से भी कम है।

वर्तमान में (२०११ की जनगणना के अनुसार) उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की लगभग १७% आबादी शहरी इलाकों में रहती है जबकि मैदानी जिलों में ४२% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आय स्तर में भी असमानता है। अधिकांश आर्थिक अवसर भी राज्य के तीन मैदानों जिलों में हैं जो स्पष्ट आर्थिक असमानता को दर्शाता हैं। बागेश्वर, चंपावत, टिहरी और अल्मोड़ा जिलों में प्रतिव्यक्ति आय देहरादून और हरिद्वार जिले की प्रतिव्यक्ति आय के आधे से भी कम है। इस प्रकार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के बहु–क्षेत्रीय विकास, पलायन की समस्या को कम करने के लिए एक सुनियोजित पहल हो सकती है और ऐसे क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है।

उत्तराखंड में पलायन की समस्या के समाधान, रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलो में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखंड सरकार ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग कार्यालय मेमो नंबर 1357/XI/17/56(54)2017 दिनांक 25/8/2017 (अनुलग्नक ०१) के गठन को सुनिश्चित किया है।

संरचना

आयोग की संरचना निम्नवत है:

1.	अध्यक्ष	:	मुख्यमंत्री
2.	उपाध्यक्ष	:	एक
3.	सदस्य	:	पांच
4.	सदस्य सचिव	:	प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण विकास
5.	अपर सदस्य सचिव	:	अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास

यदि आवश्यक हो, तो आयोग अपनी बैठकों में विशेष आमंत्रित लोगों के रूप में विभिन्न विभागों के अधिकारीगणों को विषय विशेषज्ञों के रूप में आमंत्रित कर सकता है। आयोग का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास विभाग होगा।

कार्यों का उल्लेख

उत्तराखंड सरकार द्वारा अधिसूचित आयोग की कार्यवाही नं 1720/11/17/56(54) 2017TC दिनांक 4/12/2017 (अनुलग्नक ०२) के अनुसार है:

1. राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का आंकलन करना।
2. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टीकोण विकसित करना जो पलायन की गंभीरता को कम कर ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।
3. जमीनी स्तर पर बहु–क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार को सलाह प्रदान करना जो जिला और राज्य स्तर पर सयुंक्त रूप से हो।
4. राज्य की आबादी के उन वर्गों के लिए जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हैं हेतु लघु/मध्यम/दीर्घ अवधि की कार्य योजना की सिफारिशें प्रस्तुत करना।
5. विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रित पहल की सिफारिशें और निगरानी करना जो ग्रामीण क्षेत्रों के चौमुखी विकास में सहायक होकर पलायन को रोकने में सक्षम हो।
6. राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी भी अन्य मामलो में सिफारिशें प्रस्तुत करना।

प्रतिवेदन की व्यापकता

वर्तमान प्रतिवेदन की व्यापकता इस प्रकार है:

1. राज्य में पलायन और संबंधित सामाजिक–आर्थिक स्थिति की वस्तु–स्थिति पर मौजूदा जानकारी का संक्षिप्त अवलोकन करना।
2. जिला और खंड के अनुसार गांवों से पलायन के कारणों और आयामों का सारांश तथा प्रवासियों के गंतव्य की जानकारी मुहैया करना।
3. जिन गांवों की जनसंख्या घट रही है और वहां बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, निर्जन गांवों/बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का जिला और खंडवार सारांश तैयार करना।
4. उन गांवों/बस्तियों का जिला और खंडवार सारिणी बनाना जहाँ परिवार बाहर के क्षेत्रों से आकर बस गए हैं।

उम्मीद की जाती है कि आयोग की यह पहली रिपोर्ट राज्य सरकार और ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग को इस चुनौती से निपटने के लिए एवं आगे बढ़ने के लिए मूल्यवान निविष्टियाँ प्रदान करेगी।

कार्यप्रणाली

आयोग की पहली प्रतिवेदन की तैयारी के लिए अपनाई गयी निम्नलिखित पद्धति को नीचे उल्लिखित किया गया है:

1. राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण इलाकों में स्थानीय समुदायों के साथ उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के बारे में संवाद हासिल करने; जिसमे उपलब्ध बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाएं तथा पलायन से संबंधित मुद्दों; उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं के लिए व्यापक विचार–विमर्श किया गया।

2. ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन के विषय पर नागरिको, उद्यमियों, विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, मीडिया, राज्य के सभी जिलों के अन्य हितधारको से गांवों से संबंधित मुद्दों में बुनियादी ढांचे की स्थिति एवं उनकी धारणा के संबंध में परामर्श भी आयोजित किये गए। उपाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोग की टीम ने राज्य के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया तथा पलायन और संबंधित मामलों से जुडी जमीनी स्तर की वास्तविकता एवं स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया। यह कार्य आयोग द्वारा नवंबर २०१७ से फरवरी २०१८ तक की अवधि में किया गया था।

3. २०११ के बाद की जनगणना के आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, राज्य के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर में पलायन और संबंधित सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया। आयोग ने हितधारकों, ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों एवं भारतीय वन सर्वेक्षण और एनएसएसओ (भारत सरकार) के सांख्यिकीविद् से परामर्श के बाद एक प्रश्नावली तैयार की; जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर अभिलेख एवं अनुभव आधारित जमीनी स्तर की जानकारी एवं राजस्व गांवों/तोक की संबंधित जानकारी को संग्रहण किया जा सके। यह सर्वेक्षण राज्य ग्रामीण विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से पूरे राज्य में जनवरी और फरवरी २०१८ के महीने में आयोजित किया गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों को विभिन्न संस्थाओ की सहायता से संग्रहण और विश्लेषण किया गया; जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, भारत सरकार मुख्य है।

4. माध्यमिक जानकारी विभिन्न संस्थाओ और सरकारी विभागों की प्रकाशित और अप्रकाशित विवरणियो से प्राप्त की गई है।

5. वर्तमान रिपोर्ट ऊपर सूचीबद्ध पद्धति के माध्यम से प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक जानकारी के आधार पर तैयार की गई है।

अध्याय ०२

उत्तराखंडः भूमिका

उत्तराखंड का क्षेत्रफल ५३४८५ वर्ग किलोमीटर है तथा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। इस राज्य की हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ अंतरराज्यीय सीमाएं है और चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। राज्य के पहाड़ी जिलों (अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी) का क्षेत्रफल ४५१२५ वर्ग किमी है जबकि मैदानी जिलों (देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर) में लगभग ८३६० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उत्तराखंड राज्य को दो प्रशासनिक प्रभागों में बांटा गया है जिनमें १३ जिले, १०२ तहसील, ६५ विकास खंड, ६७० न्याय पंचायतें, ७६५० ग्राम पंचायतें हैं। राज्य में १६७६३ जनगणना गांव (२०११ जनगणना) हैं जिनमें से १५७४५ बसे हुए हैं और १०४८ निर्जन (२०११ जनगणना) हैं। २००१ और २०११ की जनगणना में राज्य के गांवों की संख्या निम्न तालिका में दी गई हैः

जनसंख्या आकार वर्ग के गांव – उत्तराखंड

(जनगणना २००१ और २०११)

Population Size Class	No. Of Villages	
	2001	**2011**
Total No. of Inhabited Villages	15761	15745
Less than 200	7775	7823
200-499	4912	4684
500-999	1890	1826
1000-1999	752	824
2000-4999	350	471
5000-9999	69	96
10000 and above	13	21

स्रोतः जनगणना २०११

जनसांख्यिकी

२०११ की जनगणना के अनुसार, राज्य की आबादी १००.८६ लाख है, जिसमें ५२% से अधिक जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में रहती है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग १५.६३% हैं।

Population	48.41lakhs	52.67 lakhs	101.08 lakhs
Population growth rate% 2001-2011	0.70	2.82	1.74
Sex ratio (all age groups)Females to Males	1037	900	963

Sex ratio (0-6 years)	894	888	890
Rural population %	82.94	57.57	69.45.
Growth in urban population	2.43	3.81	3.42
Literacy rate%	80.87	76.90	78.82

(स्रोतः जनगणना २०११ और ममगाईं और रेड्डी २०१५)

जलवायु

उत्तराखंड में जलवायु स्थितियां गंगा के मैदानों के किनारे और उप–माउंटन भूभाग में उपोष्णकटिबंधीय से मुख्य हिमालयी के ऊपरी भाग में उप–आर्कटिक और आर्कटिक में तबदील होती हैं। तीन अलग–अलग मौसम होते हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। शरद ऋतु और वसंत ऋतु; वर्षा और शीत ऋतु तथा शीत और ग्रीष्म ऋतु के बीच में मौसम के परिवर्तनकाल को चिन्हित करता है। उत्तराखंड की औसत वार्षिक वर्षा लगभग १३० सेमी है जिसका बड़ा कारण मानसून के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून का प्रभाव होता है। गर्मियों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में तापमान ४४ डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है जबकि सर्दियों में ऊँची चोटियों पर हिमांक बिंदु से नीचे गिर जाता है। पश्चिमी गड़बड़ी या स्थानीय प्रभावों के कारण सर्दियों में बारिश होती है जबकि राज्य की ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होती है। बहुत ऊँचाई वाले क्षेत्र स्थायी बर्फ के आवरण से ढके हैं।

कृषि और बागवानी

बागवानी और पशुधन पालन सहित कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का मुख्य व्यवसायहै।हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान काफी कम हो गया है। २०१४–१५ में मुख्य अनाज चावल, गेहूं, जौ, मक्का और मंडुवा (डीईएस, २०१५–१६) का शुद्ध बोया गया क्षेत्र ७०००७१ हेक्टेयर था।

मुख्य दालें उरद, मसूर, राजमा, गहत, चना और काले सोयाबीन थे। अन्य प्रमुख फसलों में गन्ना, सफेद सरसों, सरसों, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। २०१५–१६ (डीईएस २०१५–१६) में प्रमुख फसलों की उत्पादकता निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

Crop	Productivity (in quintals per hectare)
Rice	23.41
Wheat	22.58
Barley	09.83
Maize	16.96
Manduwa	14.02
Urad	06.32
Masoor	07.29
Peas	09.79
Gahat	08.68
Rajma	10.19
Gram	08.40

Black soyabean	10.0
Sugarcane	607.69
Onion	51.73

उत्तराखंड में विशेष रूप से पहाड़ी जिलों में औसत प्रति व्यक्ति भूमि स्वामित्व कम हैंः एक हेक्टेयर से भी कम हैं। नीचे दी गई तालिका में यह स्पष्ट हैं। (डीईएस २०१०–११)

Category	Number	Total area in hectares
Marginal holdings less than 1 hectare	6,72,000	2,96,000
Small holdings between 1 to 2 hectares	1,57,000	2,25,000
Semi-medium and medium holdingsbetween 2 to 10 hectares	82,000	2,70,000
Large holdings more than 10 hectares	1000	25,000

फल और सब्जियां

२०१४–१५ में, फलों के तहत २,०४,६५६ हेक्टेयर क्षेत्र से ७,८५,६६५ टन का उत्पादन हुआ है। मुख्य फल में आम, लिची, अमरूद, सेब, नाशपाती और खुबानी शामिल हैं। सब्जियों के तहत ७२,३३६ हेक्टेयर क्षेत्र से ६,५७,१५७ टन का उत्पादन हुआ हैं। मुख्य सब्जियां टमाटर, फूलगोभी, सेम की फली, बैंगन इत्यादि हैं। राज्य में आलू के उत्पादन में २८,३६० हेक्टेव्स क्षेत्र से ४,५२,४६५ टन का उत्पादन हुआ।

वन

उत्तराखंड एक वन समृद्ध राज्य हैं। जिसमें अलग–अलग प्रकार के वन हैं। तराई–भाबर में उप उष्णकटिबंधीय वन हैं; ऊंची चोटियों में अल्पाइन एवं तलहटी में समशीतोष्ण वन हैं। ये जंगल ग्रामीण आबादी के लिए चारा और ईंधन लकड़ी का एक प्रमुख स्रोत हैं। राज्य में कुल दर्ज वन क्षेत्र (आईएसएफआर २०१७) के अनुसार ३८००० वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग ७१.०५% हैं। राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र २६५४७ वर्ग किलोमीटर है; जिसमे से राज्य वन विभाग के नियंत्रण और प्रबंधन के तहत २४२६५ वर्ग किलोमीटर हैं। वन पंचायतों के तहत २२४८ वर्ग किलोमीटर और३४ वर्ग किमी आरक्षित वन अन्य संस्थानों के नियंत्रण में हैं।

उत्तराखंड में संरक्षित वनों के तहत ६८८५ वर्ग किमी क्षेत्र हैं; राज्य वन विभाग के नियंत्रण और प्रबंधन के तहत ६६ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हैय ४७६६ सिविल सोयाम वन के तहत और ४६६२ गांव के जंगलों के रूप में ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में हैं। नगरपालिका और छावनी बोर्डों के नियंत्रण में १२४ वर्ग किलोमीटर के निजी वन हैं। अन्य वनों के अंतर्गत का क्षेत्र १५६८ वर्ग किमी है। २०१५–१६ में वनों से अनुमानित काष्ठ भांडार २,०१६,१८६ घन मीटर था। जंगल से प्राप्त मुख्य उत्पादों में काष्ठ, लीसा, चारा, ईंधन की लकड़ी और औषधीय पौधोंहोते हैं।

उत्तराखंड राज्य वन्यजीव में भी समृद्ध है इसमें मुख्य रूप से बाघ, तेंदुए, हाथी, कस्तूरी हिरण, काला भालू, सुस्ती भालू और भूरे भालू हैं। इसमें ०६ राष्ट्रीय उद्यान और ०७ अभयारण्य हैं जो लगभग ७६०५ वर्ग किमी क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं।

जनपद रूपरेखा

Name of district	Population in lakhs (2011 census)	Districts share in states population (%)	Percentage of urban population(2011 census) *	Area in sq kms.	Percentage of state's geographical area
Almora	6.22	6.15	10.02	3090	5.78
Bageshwar	2.59	2.57	3.50	2310	4.32
Chamoli	3.91	3.87	15.11	7692	14.38
Champawat	2.59	2.56	14.29	1781	3.33
Dehradun	16.99	16.79	55.90	3088	5.77
Hardwar	19.2	19.05	33.77	2360	4.41
Nainital	9.56	9.44	38.94	3853	7.20
Pauri	6.86	6.79	16.41	5348	10.17
Pithoragarh	4.86	4.80	14.31	7110	13.29
Rudraparyag	2.37	2.34	4.19	1896	3.55
Tehri	6.16	6.09	11.37	4085	7.64
Udhamsingh Nagar	16.48	16.29	35.58	2912	5.44
Uttarkashi	3.29	3,26	7.35	7971	14.87

*राज्य शहरी आबादी ३०.५५: (२०११ जनगणना) हैं।

राज्य और जिला घरलू उत्पाद/प्रति व्यक्ति आय

राज्य घरलू उत्पाद का स्थिर भावो पर वर्ष २०११–१२ में १०१९६० करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया हैं। वर्ष २०१२–१३ में १०६५२८ करोड़ रुपये, वर्ष २०१३–१४ में ११७७७८ करोड़ रुपये, वर्ष २०१४–१५ में १२७०७०२ करोड़ रुपये, २०१५–१६RE के लिए १३५७२५ करोड़ रुपये और वर्ष २०१६–१७PE के लिए १४५१३८ करोड़ रुपये का अनुमानित अनुमान है। प्रतिशत वृद्धि के मामले में राज्य घरलू उत्पाद का स्थिर भावों वर्ष २०१२–१३ में ७.४२%, वर्ष २०१३–१४ में ७.५३%, वर्ष २०१४–१५ में ६.७३%, वर्ष २०१५–१६RE में ७.९७% और २०१६–१७PE में ६.९४% क्रमशः पिछले वर्ष के संबंध में वृद्धि हुई। (डीईएस २०१५)

अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना

अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में विभाजित है – प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में फसल, पशुधन, वानिकी और लॉगिंग, मत्स्य पालन और खनन शामिल हैं। माध्यमिक क्षेत्र में विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं और निर्माण शामिल हैं। जबकि तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, भंडारण, संचार, प्रसारण, व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, आवास और व्यावसायिक सेवाओं के स्वामित्व, लोक प्रशासन और अन्य सेवाओं से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।

मौजूदा मूल्यों पर पिछले वर्ष के दौरान जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में वार्षिक वृद्धि:

नीचे दी गई तालिका पिछले मूल्यों पर जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में वार्षिक वृद्धि दर्शाती है (डीईएस २०१५ और २०१८)

Year	GSDP	Per capita GSDP
2012-13	14.12	12.60
2013-14	13.27	11.76
2014-15	8.29	6.85
2015-16 RE	9.13	7.68
2016-17 PE	10.80	9.32

२०१४–१५ और २०१५–१६ में गिरावट आई है, हालांकि २०१६–१७ के लिए PE बढ़ती प्रवृत्ति दिखाती है।

मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी में क्षेत्रवार योगदान (डीईएस२०१५ और २०१८)

Sector	% Contribution in 2011-12	% Contribution in 2016-17 PE	% Contribution in 2017-18PE
Primary	14.00	11.19	10.50
Secondary	52.13	50.40	49.74
Tertiary	33.88	38.41	39.76
State GSDP	100	100	100

विभिन्न क्षेत्रों (डीईएस २०१५ और २०१८) के घरेलू उत्पाद (वर्तमान कीमतों पर) में जिलावार प्रतिशत योगदान

Name of district	Primary sector 2004-05	Secondary sector 2004-05	Tertiary sector 2004-05	Primary sector 2013-14	Secondary sector 2013-14	Tertiary sector 2013-14
Almora	37.61	18.79	43.61	27.88	20.09	52.03
Bageshwar	39.24	21.43	39.33	31.82	21.20	46.98
Chamoli	37.16	24.50	38.34	25.87	31.43	42.70
Champawat	42.78	17.60	39.62	26.27	18.79	54.94
Dehradun	11.71	22.88	65.42	6.37	27.47	66.16
Haridwar	19.07	34.64	46.29	13.05	44.83	42.13
Nainital	25.38	21.46	53.16	15.54	29.00	55.46
Pauri	24.69	23.34	51.97	15.59	30.24	54.17
Pithoragarh	30.20	24.35	45.45	23.59	24.37	52.04
Rudraparyag	30.60	22.71	46.69	25.22	21.32	53.46
Tehri	26.71	29.57	43.72	19.43	30.80	49.78
Udhamsingh Nagar	19.48	35.67	44.85	14.84	48.76	36.39

Uttarkashi	42.96	16.75	40.29	31.91	19.32	48.77
Uttarakhand	23.48	27.02	49.50	15.61	35.06	49.34

जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तेजी से घट रहा है और अब यह ११.१६% (२०१६–१७ में) तक पहुंच गया है; और २०१७–१८ में और गिरावट आने की उम्मीद है।

२०१६–१७ में राज्य स्तर पर प्राथमिक क्षेत्र में उप–क्षेत्रीय विभागों का मुख्य योगदान निम्नलिखित तालिका (डीईएस २०१८) में दिया गया है:

Sub sector	Percentage contribution	Growth rate (%) at current prices
Agriculture and Horticulture	44.10	2.70
Animal Husbandry	25.10	9.04
Forestry and allied activities	16.70	-3.82
Fisheries	0.30	6.11
Mining etc	13.65	13.65

कृषि की वृद्धि दर कम है हालांकि ग्रामीण आबादी की अपनी आजीविका के लिए प्रमुख निर्भरता कृषि ही है।

२०१६–१७ के दौरान कृषि और बागवानी (प्रतिशत में) के लिए विभिन्न गतिविधियों का योगदान नीचे दिया गया है (डीईएस २०१८):

Component	Percentage contribution
Cereal	32.39
Fruits	21.32
Sugar cane	17.03
Vegetables	8.62
Condiments	4.49
Pulses	3.32
Others including flowers, oil seeds, miscellaneous crops etc.	12.83

राज्य/जिलावार घरेलू उत्पाद (मौजूदा कीमतों पर लाख रुपये में) (डीईएस २०१५ और २०१८)

Name of district	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2016-17 PE
Almora	351388	417537	476363	532475	609156	660378
Bageshwar	108062	133938	157672	177158	201175	326782
Chamoli	252969	297199	335188	381241	439764	573115
Champawat	128929	137600	161534	181317	207738	287786

Dehradun	1227110	1538934	1769011	1957850	2225255	4057583
Hardwar	1397438	1873884	2206406	2406172	2718945	5816824
Nainital	695806	830163	977119	1074083	1218987	1345261
Pauri	406863	500043	576353	639824	731168	828356
Pithoragarh	254264	313773	351276	393419	450597	603799
Rudraparyag	104908	128336	150648	168958	191750	251040
Tehri	345110	437485	514066	574358	655364	647262
Udhamsingh Nagar	1249823	1623364	1921032	2087629	2349013	3759811
Uttarkashi	145654	164640	189103	212350	244417	361225
Uttarakhand	6668324	8396895	9785772	10786835	12243330	21760900

पहाड़ी जिलो जैसे की अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी का जिलावार सकल घरेलू उत्पाद मैदानी जिलों देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के ४०% से भी कम है। यह शायद उनकी अपेक्षाकृत कम आबादी और काफी हद तक ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था के कारण है। जब हम २००६–१० और २०१६–१७ के बीच राज्य के पहाड़ी और मैदानी जिलों के सकल घरेलू उत्पाद के विकास की अनुमानित दर की तुलना करते हैं, तो पहाड़ी जिलों में यह ०२ या २.५ गुना बढ़ गया है और ०३ गुना या उससे अधिक मैदानी जिलों में बढ़ गया है।

पहाड़ी जिलों में प्राथमिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान राज्य की औसत से कहीं अधिक है। भले ही यह गिरावट की प्रवृत्ति दिखा रहा हो। यह प्राथमिक क्षेत्र पर पहाड़ी जिलों में रहने वाले लोगों की निर्भरता, मुख्य रूप से कृषि और उनकी आजीविका के लिए संबद्ध गतिविधियों की निर्भरता को इंगित करने का एक और सबूत है। २०१३–१४ में, देहरादून जिले का सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ६.३७% था; जो की राज्य औसत १५.६१% का आधे से भी कम था।

सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की जिलावार दर (निरंतर कीमतों पर % में) (डीईएस २०१५ और २०१८)

Name of District	2009-10	2010-11	2012-12	2012-13	2013-14	2016-17 (as 2011-12 prices)
Almora	13.75	9.45	7.01	4.77	6.60	6.49
Bageshwar	9.62	12.76	9.49	4.93	6.69	6.46
Chamoli	10.08	-0.49	6.11	4.48	7.20	6.23
Champawat	10.53	-6.63	11.22	5.28	6.51	5.75
Dehradun	11.33	16.43	9.16	5.77	6.22	7.62
Hardwar	11.46	22.08	9.81	5.73	4.81	7.29
Nainital	13.75	10.87	10.52	5.88	5.73	6.79
Pauri	11.60	12.56	8.91	5.40	6.17	6.79

Pithoragarh	12.19	16.86	1.28	4.62	6.78	6.73
Rudraparyag	10.44	19.47	10.48	5.12	6.88	6.49
Tehri	11.96	16.92	10.33	4.99	7.33	7.03
Udhamsingh Nagar	11.34	23.24	11.05	6.11	4.51	6.49
Uttarkashi	6.86	0.82	5.12	4.60	6.96	6.06
Uttarakhand	11.61	16.44	9.37	5.61	5.65	6.95

२००९–१० और २०१३ के बीच राज्य के सभी जिलों की वार्षिक वृद्धि दर में कमी आई है। चमोली और चंपावत जिलों ने वर्ष २०१०–११ में नकारात्मक वृद्धि दर थी। पहाड़ी जिलों के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की वार्षिक दर मैदानी जिलों की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी है, खासकर चमोली, चंपावत और उत्तरकाशी जिलों में।

जिलावार प्रति व्यक्ति आय (रुपये में) (डीईएस २०१५ और २०१८)

Name of District	**2010-11**	**2012-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2016-17**
Almora	59,000	67701	75474	86,699	96,786
Bageshwar	46,194	54360	60646	68,730	1,00,117
Chamoli	62,269	69543	78371	90,173	1,18,448
Champawat	49,793	11.22	57990	64165	90,595
Dehradun	89,282	1,01,315	1,09,695	1,22,804	1,95,925
Hardwar	88,980	1,03,836	1,10,115	1,22,172	2,54,050
Nainital	96,950	89,102	95,227	1,05,960	1,15,117
Pauri	62,354	72,228	79,904	91,708	1,09,973
Pithoragarh	56,458	63,045	69,994	79,981	1,01,734
Rudraparyag	47,459	55,495	61,561	69,401	83,521
Tehri	58,496	68,282	75,249	85,156	83,662
Udhamsingh Nagar	85,541	1,00,058	1,05,087	1,15,543	1,87,313
Uttarkashi	42,079	47,755	52,574	59,791	89,190
Uttarakhand	73,819	85,372	92,191	1,03,349	1,61,102

पहाड़ी जिलों में प्रति व्यक्ति आय मैदानी जिलों की तुलना में काफी कम है, जिन जिलों में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। वे बागेश्वर, चंपावत और उत्तरकाशी है। जहां प्रति व्यक्ति आय उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के मैदानी जिलों में से लगभग ४०% है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि इन जिलों के सकल घरेलू उत्पाद, विशेष रूप से उत्तरकाशी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राज्य औसत से काफी अधिक है।

संदर्भ

1. जनगणना २०११ – उत्तराखंड, जनगणना २०११, कार्यालय रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत नई दिल्ली।
2. डीईएस २०१५ – उत्तराखंड के जिला घरेलू उत्पाद का अनुमान, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखंड सरकार, देहरादून।
3. डीईएस २०१५–१६ – उत्तराखंड एक नजर , अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखंड सरकार, देहरादून।
4. डीईएस २०१८ – उत्तराखंड के जिला घरेलू उत्पाद का अनुमान, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखंड सरकार, देहरादून।
5. आईएसएफआर २०१७ – भारत – वन स्थिति रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारत सरकार, देहरादून।
6. ममगाईं और रेड्डी (२०१५) उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन, परिमाण, चुनौतियां और नीति विकल्प, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, हैदराबाद।

अध्याय ०३

पलायनः ऐतिहासिक भूमिका

पलायन का मतलब निवास के स्थान का स्थायी या अर्द्ध स्थायी परिवर्तन है (ली १९६६)। मैकलेमन (२०१७) के अनुसार काम करने के लिए यात्रा, छुट्टी पर जाना या एक ही शहर में दूसरे प्रकोष्ठ में जाना ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन्हें आम तौर पर पलायन नहीं माना जाता है (लेकिन 'गतिशीलता' की एक बहुत व्यापक अवधारणा का हिस्सा हैं)। पलायन मौसमी, अस्थायी (लेकिन मौसमी नहीं) या अनिश्चित (या स्थायी) हो सकता है (गोंजालेज १९६१)। पलायन अक्सर स्थानिक स्वरूप का पालन करता है। हालांकि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में यह सबसे आम है। शहरी–ग्रामीण प्रवासन भी होता है हालांकि यह कम है। अन्य रूप ग्रामीण–ग्रामीण प्रवासन और शहरी–शहरी प्रवास हो सकते हैं (मैकलेमन इबिड)। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कम आय से उच्च आय वाले देशों में लोगों का प्रवास प्रति वर्ष लगभग ०४ मिलियन है (यूएन डीईएसए २०१५)।

एनएसएसओ (२०१०) के अनुसार भारत में आंतरिक प्रवासियों का पलायन लगभग ३०९ करोड़ है; जो २००१ में देश की कुल जनसँख्या का लगभग ३०% है। १९५१ में भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत कुल जनसंख्या का केवल १७% था; जो की २०२५ तक कुल जनसंख्या का लगभग ४२.५% तक पहुंचने की उम्मीद है। यह सब इसलिए होगा क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण इलाकों को छोड़ देंगे। पिछले ५० वर्षों में, ग्रामीण आबादी में ८२.० से ६८.९% (रजी २०१४) की कमी आई है।

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ११वीं और १२वीं शताब्दी के दौरान भारत के अन्य हिस्सों से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है (एटकिंसन १८८२ और वाल्टन १९१०)। ये शायद मैदानी इलाकों में आक्रमणकारियों द्वारा अभियोजन पक्ष के निपटारे और तीर्थयात्रा पर आए तीर्थयात्रियों के स्थायीकरण के कारण था। अगली कई शताब्दियों में कठिन श्रम के माध्यम से वनों को खेती के लिए परिवर्तित किया गया। ११वीं शताब्दी से पहले इन इलाको में शायद बड़े पैमाने पर खानाबदोश चरागाह समुदायों द्वारा निवास किया गया था; हालांकि खेती की शुरूआत भी शुरू हुई थी, जिसका विस्तार ११वीं और १२वीं सदी में बड़े पैमाने पर हुए पलायन के बाद हुआ।

१९वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के मजबूत होने और गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट को बढ़ाने और पुलिस सहित अन्य सरकारी सेवाओं में अवसरों के साथ, स्थानीय युवाओं को नियमित रोजगार मिलना शुरू हो गया और पलायन हुआ; हालांकि उनमें से अधिकांश सेवानिवृत्ति के बाद लौटे और कईयों ने अपने परिवारों को खेती के लिए गांवों में भी रखा। वाल्टन (१९१०) भी इस बारे में उल्लेख करते है की आजीविका की खोज में पहाड़ो से मैदानी इलाकों में मौसमी पलायन भी हुए है।

उत्तराखंड में जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन

दशकीय परिवर्तन जनसंख्या में १९०१ (उत्तराखंड)

नीचे दी गई तालिका १९०१ से उत्तराखंड की आबादी में दशकीय परिवर्तन दिखता है। राज्य की आबादी में १९११ और १९२१ के बीच मुख्य रूप से चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में कमी हुई है।

State/Union Territory /District	Census/ Year	Persons	Variation since the preceding census		Males	Females
			Absolute	Percentage		
Uttarakhand	1901	1,979,866	----	----	1,032,166	947,700
	1911	2,142,258	+162,392	+8.20	1,123,165	1,019,093
	1921	2,115,984	-26,274	-1.23	1,104,586	1,011,398
	1931	2,301,019	+185,035	+8.74	1,202,594	1,098,425
	1941	2,614,540	+313,521	+13.63	1,371,233	1,243,307
	1951	2,945,929	+331,389	+12.67	1,518,844	1,427,085
	1961	3,610,938	+665,009	+22.57	1,854,269	1,756,669
	1971	4,492,724	+881,786	+24.42	2,315,453	2,177,271
	1981	5,725,972	+1,233,248	+27.45	2,957,847	2,768,125
	1991	7,050,634	+1,324,662	+23.13	3,640,895	3,409,739
	2001	8,489,349	+1,438,715	+20.41	4,325,924	4,163,425
	2011	10,086,292	+1,596,943	+18.81	5,137,773	4,948,519

स्रोतः उत्तराखंड, जनगणना २०११

जनसंख्या का जिलावार दशकीय परिवर्तन

निम्नलिखित तालिका जनसंख्या में जिलावार दशकीय परिवर्तन दिखाता है (जनगणना का आधार; १९८१; १९९१; २००१ और २०११) २००१ और २०११ के बीच अल्मोड़ा और पौड़ी जिलों की आबादी में कमी आई है।

Districts	1981 % Increase	1991 % Increase	2001 % Increase	2011 % Increase/Decrease
Almora	15.81	8.94	3.67	-1.73
Bageshwar	19.57	14.81	9.28	5.13
Chamoli	24.15	22.63	13.87	5.6
Champawat	25.34	26.38	17.6	15.49
Dehradun	31.93	34.66	25.00	32.48
Haridwar	32.72	26.31	28.70	33.16
Nainital	38.08	30.22	32.72	25.20
Pauri	15.46	8.57	3.91	-1.51
Pithoragarh	16.38	14.11	10.95	5.13
Tehri	24.67	16.53	16.24	1.93
Udhamsingh Nagar	48.05	38.30	33.60	33.40
Uttarkashi	29.19	25.54	23.07	11.75
State	27.45	23.13	20.41	19.17

स्रोतः भारतीय जनगणना निर्दिष्ट

१९८१ और २०११ में दशकीय वृद्धि विभिन्न जिलों में धीमी हुई है; यह आंकड़ा पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में नकारात्मक है और टिहरी जिले में अपेक्षाकृत कम है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, अध्ययन

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा उत्तराखंड में पलायन पर किए गए विस्तृत अध्ययन के नतीजे (ममगाईं एवं रेड्डी २०१५) नीचे दिए गए अंकों में सारांशित किये गए है:

1. अधिकांश आर्थिक अवसर राज्य के मैदानी क्षेत्रों में संकेन्द्रित हुए, जिससे राज्य के पहाड़ी और मैदानी जिलों में भारी आय असमानताएं आईं। बागेश्वर, चंपावत, टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा जिलों में प्रति व्यक्ति आय (जो प्रति व्यक्ति जिला सकल घरेलू उत्पाद में मापा जाता है) देहरादून और हरिद्वार से लगभग आधा है।

2. २००१–११ की अवधि के दौरान उत्तराखंड में उच्च आर्थिक वृद्धि देखी गई; जिसमें जनसंख्या वृद्धि १.७४% प्रतिवर्ष थी; जो राष्ट्रीय औसत से अधिक थी; हालांकि पहाड़ी जिलों में यह आंकड़ा ०.७०% था; और मैदानी जिलों में यह २.८२% था। इसके अलावा, पहाड़ी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर ०.३८% से भी कम थी; हालांकि पहाड़ी जिलों के शहरी इलाकों के लिए यह आंकड़ा अधिक है।

3. मैदान जिलों की तुलना में पहाड़ी जिलों का लिंग अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है; हालांकि बाल लिंग अनुपात पहाड़ी और मैदानी जिलों में लगभग बराबर है; जो अधिक वयस्क पुरुषो का पहाड़ी जिलों से दूर जाने की प्रवृत्ति का संकेत देता है।

4. अल्मोड़ा और पौड़ी जिलों की जनसंख्या में परिवर्तन से यह उभरता है; कि जनसंख्या में पूर्ण गिरावट छोटे गांवों में रही है; जबकि इन दोनों जिलों के १२५ से अधिक परिवारों के बड़े गांवों में जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक रही है।

5. उत्तराखंड में पलायन आमतौर पर लंबी अवधि का होता है और मुख्य रूप से राज्य से बाहर के साथ–साथ बड़े शहरों और कस्बों के लिए भी होता है। यह लंबी अवधि के प्रवासियों का तीन–चौथाई पलायन रिपोर्ट करता हैं। प्रवासियों का लगभग दसवां हिस्सा ०२ से ०६ महीने की कम अवधि के लिए प्रवासित होता है। यह कई अध्ययनों में देखे गए स्वरूप के विपरीत है जो देश के अन्य हिस्सों के ग्रामीण परिवारों के बीच अल्प अवधि के प्रवासन की पूर्वनिर्धारितता–ज्यादातर चक्रीय प्रकृति को रिपोर्ट करता हैं (श्रीवास्तव, २०११; यूनेस्को, २०१३)। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण भी है कि उत्तराखंड से बाहर प्रवासियों का बहुमत (लगभग ७४ प्रतिशत) सरकारी या निजी क्षेत्रों की नौकरियों में वेतनभोगी है जो आम तौर पर लंबी अवधि के होते हैं। बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण प्रवासियों के विपरीत कृषि में अल्पकालिक रोजगार के लिए वे कृषि समृद्ध क्षेत्रों में स्थानांतरित नहीं होते हैं (ममगाईं, २००४)। शायद; उनकी अपेक्षाकृत बेहतर शैक्षिक योग्यता उन्हें वेतनभोगी नौकरियां पाने में मदद करती है; हालांकि अधिकांश बहुत अधिक आय वाले नहीं है।

6. इस एनआईआरडी अध्ययन में यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि कई प्रवासियों के पास बेहतर शिक्षा है; और उन्हें नियमित रूप से वेतनभोगी नौकरियां मिलती हैं; जो पहाड़ी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं। परिवारों के पास अपने सदस्यों; मुख्य रूप से नर के शैक्षणिक स्तर को सुधारने की प्रवृत्ति है; ताकि वे पहाड़ी क्षेत्र के बाहर रोजगार प्राप्त कर सकें। मुख्य रूप से इस कारण प्रवासियों का दसवां हिस्सा

पहले अपने शिक्षा स्तर में सुधार के लिए आगे बढ़ता है; और फिर नौकरी पाने के बाद लंबी अवधि के प्रवासियों में बदल जाता है। लगभग २०% श्रमिक शहरी क्षेत्रों में बेहतर आर्थिक संभावनाओं के लिए प्रवास करते हैं। प्रवासन का यह स्वरूप व्यक्तिगत संपर्कों द्वारा भी होता है और दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच उदाहरण बनता है।

7. पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन की कठिनाइयों जैसे खराब सड़कों, पर्याप्त जल आपूर्ति की कमी और खराब शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं से भी पलायन की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

8. उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के प्रवासियों ने गांवों में अपने परिवारों की घरेलू आय में प्रेषण के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है; जो गरीब परिवारों में लगभग ५०% है; और कम आय वाले समूह के घरों में ३८% होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय स्तर पर तुलना

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने जुलाई २००७ और जून २००८ के बीच रोजगार, बेरोजगारी और प्रवासन विवरणों पर ६४वें दौर के सर्वेक्षण का आयोजन किया, जिसमें रिपोर्ट जून २०१० में प्रकाशित की गई थी। एनएसएसओ २०१० द्वारा देश के लिए मुख्य निष्कर्ष हैं:

क. पिछले ३६५ दिनों के दौरान घरेलू पलायन

1. ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित परिवारों का अनुपात बहुत कम था, लगभग ०१ प्रतिशत। दूसरी ओर, शहरी इलाकों में प्रवासित परिवारों ने शहरी परिवारों का लगभग ०३ प्रतिशत गठित किया।

2. कई परिवारों का प्रवास बड़े पैमाने पर राज्य के भीतर ही सीमित था। ग्रामीण इलाकों में प्रवासी परिवारों का ७८ प्रतिशत और शहरी इलाकों में प्रवासित परिवारों का ७२ प्रतिशत के निवास की पिछली सामान्य जगह राज्य के भीतर थी।

3. ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में परिवारों के प्रवासन पर ग्रामीण इलाकों के परिवारों से पलायन का प्रभुत्व था। शहरी इलाकों में लगभग ५७ प्रतिशत परिवार ग्रामीण इलाको से प्रवासित थे; जबकि २९ प्रतिशत ग्रामीण प्रवासित परिवार शहरी इलाकों से थे।

4. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, अधिकांश घर रोजगार से संबंधित कारणों से प्रवासित हुए। ग्रामीण इलाकों में लगभग ५५ प्रतिशत परिवार और शहरी इलाकों में ६६ प्रतिशत परिवार रोजगार संबंधी कारणों से पलायन कर चुके थे।

ख. प्रवासी

1. भारत में लगभग २९ प्रतिशत लोग ग्रामीण–शहरी प्रवासी थे।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासन दर अनुसूचित जनजाति (एसटी) में सबसे कम थी, लगभग २४ प्रतिशत, और यह सामाजिक समूह 'अन्य' में वर्गीकृत लोगों में सबसे ज्यादा थी, जो लगभग २८ प्रतिशत थी।

3. ग्रामीण पुरुष में 'निरक्षर' के बीच प्रवास दर सबसे कम (लगभग ०४ प्रतिशत) थी; और यह शैक्षणिक स्तर 'स्नातक और ऊपर' वाले लोगों में लगभग १४ प्रतिशत थी। शहरी पुरुषों में भी, यह 'निरक्षर' के बीच सबसे कम था (१७ प्रतिशत), और शैक्षणिक स्तर 'स्नातक या ऊपर' वाले लोगों के लिए ३८ प्रतिशत था।

4. शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों में लगभग ५६ प्रतिशत ग्रामीण इलाकों से और ४० प्रतिशत शहरी इलाकों से प्रवासित हुए।

5. शहरी पुरुष प्रवासियों का लगभग ६० प्रतिशत और शहरी महिला प्रवासियों का ५६ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित हो गया था।

6. ग्रामीण प्रवासियों के लिए पलायन का कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में रोजगार संबंधी कारणों का प्रभुत्व था। रोजगार संबंधी कारणों से ग्रामीण पुरुष प्रवासी लगभग २६ प्रतिशत और शहरी पुरुष प्रवासी ५६ प्रतिशत प्रवासित हो गए थे।

7. कुल प्रवासियों में आत्म–रोजगार का हिस्सा बढ़ गया; प्रवासन से पहले १६ प्रतिशत और प्रवासन के बाद २७ प्रतिशत तक। जबकि नियमित कर्मचारियों और आकस्मिक श्रमिकों के योगदान से प्रवासन के पहले और बाद में लगभग स्थिर रहा।

8. शहरी पुरुषों में नियमित मजदूरी/वेतनभोगी कर्मचारियों के प्रतिशत में अकस्मात वृद्धि दिखी है (१८ प्रतिशत प्रवासन से पहले और प्रवासन के बाद ३६ प्रतिशत)। प्रवासन के बाद (१७ प्रतिशत से २२ प्रतिशत) स्व–रोजगार के हिस्से में वृद्धि के अलावा, आकस्मिक श्रम का रोजगार के साधनों के रूप में महत्व कम हुआ है (११ प्रतिशत से ०८ प्रतिशत तक)।

9. वापसी प्रवास की दर (आबादी में वापसी प्रवासियों का अनुपात) ग्रामीण इलाकों में पुरुषों का महिलाओं की तुलना में काफी अधिक था; पुरुषों का २४ प्रतिशत और महिलाओं का ११ प्रतिशत।

ग. बाहर प्रवासन

1. पुरुषों के लिए बाहर प्रवासन दर (आबादी में बाहर प्रवासन का अनुपात) ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग ०६ प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों से ०५ प्रतिशत था। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की दरें बहुत अधिक थीं। यह ग्रामीण महिलाओं में १७ प्रतिशत और शहरी महिलाओं में ११ प्रतिशत थी।

2. ग्रामीण पुरुष दोनों राज्यों; जिससे वे बाहर निकल गए और साथ ही साथ राज्य के बाहर चले गए (इन दो प्रकार के स्थानों में से प्रत्येक में लगभग ४६ प्रतिशत)।

3. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में से अधिकांश पुरुष रोजगार से संबंधित कारणों से बाहर निकल गए थे। जो की ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर प्रवासन के लिए लगभग ८० प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में ७१ प्रतिशत जिम्मेदार है।

4. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला प्रवासियों के लिए, विवाह मुख्य रूप से पलायन का कारण था, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगभग ८४ प्रतिशत महिला प्रवासियों के लिए जिम्मेदार था।

5. भारत में रहने वाले ८० प्रतिशत लोगों की तुलना में विदेशों में रहने वाले ग्रामीण पुरुष प्रवासी लगभग ६५ प्रतिशत आर्थिक गतिविधियों में लगे थे और भारत में रहने वाले शहरी क्षेत्रों से ७३ प्रतिशत लोगों की तुलना में विदेश में रहने वाले प्रवासी लोग लगभग ६३ प्रतिशत आर्थिक गतिविधियों में लगे थे।

घ.बाहर प्रवासी प्रेषण

1. ग्रामीण इलाकों से विदेशों में रहने वाले पुरुष प्रवासियों में से लगभग ८२ प्रतिशत ने पिछले ३६५ दिनों के दौरान प्रेषण भेजा था, जबकि भारत में रहने वाले पुरुष प्रवासियों में से केवल ५८ प्रतिशत ने प्रेषण भेजा था।

2. शहरी क्षेत्रों से विदेशों में रहने वाले पुरुष प्रवासियों में से, लगभग ६६ प्रतिशत ने प्रेषण भेजा था जबकि भारत में रहने वाले पुरुष प्रवासियों में से केवल ४१ प्रतिशत ने प्रेषण भेजा था।

3. औसतन, पिछले ३६५ दिनों के दौरान, ग्रामीण इलाकों से विदेश में रहने वाले एक पुरुष प्रवासी ने भारत में रहने वाले एक पुरुष प्रवासी द्वारा भेजे गए प्रेषण की राशि का ०४ गुना भेजा था; औसतन लगभग रु ५२००० विदेशों में रहने वाले पुरुष प्रवासी द्वारा प्रेषित किया गया था, जबकि भारत में रहने वाले पुरुष प्रवासी के लिए राशि लगभग रु १३००० थी।

4. शहरी क्षेत्रों से बाहर प्रवासियों ने पिछले ३६५ दिनों के दौरान ग्रामीण इलाकों की तुलना में अपने पूर्व परिवारों को उच्च राशि प्रेषित की थी। औसतन शहरी क्षेत्रों से विदेशों में रहने वाले एक पुरुष प्रवासी ने लगभग रु ७३,००० पिछले ३६५ दिनों के दौरान प्रेषित की थी; जो की उच्चतर राशी प्रेषित की गयी थी; ग्रामीण इलाकों से बाहर निकलने वाले और विदेश में रहने वाले पुरुष प्रवासियों द्वारा।

5. लगभग ३० प्रतिशत ग्रामीण परिवारों ने और १६ प्रतिशत शहरी परिवारों ने अपने पूर्व सदस्यों के प्रवासन की सूचना दी थी।

6. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ता व्यय में प्रेषण का मुख्य उपयोग था। ग्रामीण इलाकों में लगभग ६५ प्रतिशत परिवार और शहरी इलाकों में ६३ प्रतिशत परिवारों ने घरेलू उपभोक्ता व्यय के उद्देश्य के लिए प्रेषण का उपयोग किया था।

7. ग्रामीण इलाकों में लगभग १० प्रतिशत परिवारों ने 'ऋण चुकौती' के लिए प्रेषण का उपयोग किया था और शहरी क्षेत्रों में लगभग १३ प्रतिशत परिवारों ने 'बचत/निवेश' के लिए प्रेषण का उपयोग किया था।

एनएसएसओ (२०१०) रिपोर्ट से निकाले कुछ उद्धरण तालिकाओं में नीचे दिए गए है। ये कुछ राज्यों में उत्तराखंड के तुलना में प्रवासन के मुख्य पहलुओं को दिखाते हैं।

प्रवासन के कारण प्रवासियों के वितरण (प्रति १०००) विभिन्न राज्यों के लिए (ग्रामीण पुरुष+महिला)

State	Reason for migration						
	Employment related reasons	Studies	Forced migration	Marriage	Movement of parent/ earning member	Others	All (incl.n.r.)
Andhra Pradesh	60	42	2	722	112	58	1000
Arunachal Pradesh	541	138	7	123	0	46	1000
Assam	23	4	66	781	61	34	1000
Bihar	4	1	5	948	6	26	1000
Chhattisgarh	48	16	1	779	75	63	1000
Himachal Pradesh	70	31	8	721	61	107	1000
Jammu &	31	3	12	904	10	38	1000

Kashmir							
Jharkhand	9	2	3	961	2	18	1000
Karnataka	32	49	8	778	86	46	1000
Kerala	57	9	2	539	172	217	1000
Madhya Pradesh	26	9	4	900	34	19	1000
Maharashtra	72	33	8	741	102	41	1000
Manipur	324	117	0	76	354	0	1000
Meghalaya	160	28	12	454	274	47	1000
Mizoram	296	24	16	95	437	57	1000
Orissa	19	28	4	883	25	36	1000
Punjab	50	8	12	823	65	35	1000
Uttarakhand	87	14	6	664	163	66	1000

स्रोतः एनएसएसओ (२०१०)

विभिन्न राज्यों(शहरो) के लिए प्रवासियों की प्रवास दर (प्रति १००० व्यक्ति)

State	Male	Female	Male+Female
Andhra Pradesh	333	467	400
Arunachal Pradesh	38	27	33
Assam	223	327	270
Bihar	208	497	345
Chhattisgarh	330	590	452
Himachal Pradesh	455	618	532
Jammu & Kashmir	97	281	186
Karnataka	265	383	324
Kerala	258	428	348
Madhya Pradesh	160	523	336
Maharashtra	356	493	421
Manipur	10	26	18
Meghalaya	42	47	44
Mizoram	189	223	206
Orissa	224	567	442
Punjab	223	565	379
Uttarakhand	397	594	486

स्रोतः एनएसएसओ (२०१०)

विभिन्न राज्यों (ग्रामीण) के लिए प्रवासियों की प्रवास दर (प्रति १००० व्यक्ति)

State	Male	Female	Male + Female
Andhra Pradesh	88	473	282
Arunachal Pradesh	11	5	8
Assam	26	227	120
Bihar	12	379	189
Chhattisgarh	70	531	295
Himachal Pradesh	153	592	378
Jammu & Kashmir	24	329	174
Karnataka	80	474	273
Kerala	195	459	333
Madhya Pradesh	30	533	268
Maharashtra	98	572	329
Manipur	6	5	6
Meghalaya	38	29	33
Mizoram	107	114	110
Orissa	43	511	280
Punjab	74	571	312
Uttarakhand	151	539	344

स्रोतः एनएसएसओ (२०१०)

विभिन्न राज्यों (पुरुष) के दौरान चार प्रकार के ग्रामीण–शहरी प्रवासन धाराओं द्वारा आंतरिक प्रवासियों के वितरण (प्रति १०००)

State	Migration streams				
	Rural to Rural	Urban to Rural	Rural to Urban	Urban to Urban	All
Andhra Pradesh	333	76	413	178	1000
Arunachal Pradesh	264	287	287	161	1000
Assam	492	35	357	117	1000
Bihar	285	54	492	169	1000
Chhattisgarh	421	95	302	182	1000
Himachal Pradesh	370	389	168	74	1000
Jammu & Kashmir	281	247	272	199	1000
Karnataka	247	142	333	279	1000
Kerala	534	169	165	133	1000
Madhya Pradesh	311	69	325	295	1000
Maharashtra	220	63	420	297	1000

Manipur	514	135	203	149	1000
Meghalaya	581	251	118	50	1000
Mizoram	328	40	333	300	1000
Orissa	336	110	309	245	1000
Punjab	269	106	417	208	1000
Uttarakhand	356	173	217	254	1000
West Bengal	273	86	332	310	1000

स्रोतः एनएसएसओ (२०१०)

विभिन्न राज्यों के लिए गतिविधियों की प्रकृति द्वारा प्रवासियों के वितरण (प्रति १०००) ग्रामीण पुरुष+महिला

Sl. No.	State	Nature of Movement			
		Temporary with duration of stay		Permanent	All (incl. n.r.)
		Less than 12 months	12 months of more		
1	Andhra Pradesh	1	93	906	1000
2	Arunachal Pradesh	29	667	203	1000
3	Assam	3	27	970	1000
4	Bihar	1	23	973	1000
5	Chhattisgarh	8	66	924	1000
6	Himachal Pradesh	3	144	853	1000
7	Jammu & Kashmir	2	39	959	1000
8	Karnataka	2	107	891	1000
9	Kerala	12	73	915	1000
10	Madhya Pradesh	1	18	980	1000
11	Maharashtra	5	84	911	1000
12	Manipur	167	738	83	1000
13	Meghalaya	0	282	711	1000
14	Mizoram	0	62	938	1000
15	Orissa	1	57	942	1000
16	Punjab	1	55	944	1000
17	Uttarakhand	6	90	904	1000

स्रोतः एनएसएसओ (२०१०)

एनएसएसओ की व्यापक रिपोर्ट से उपरोक्त सारणी का विश्लेषण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उत्तराखंड में प्रवासन के विभिन्न पहलू अन्य प्रमुख राज्यों के समान हैं।

हिमालयी राज्यों में २००१ में कुल जनसंख्या में प्रवासियों का प्रतिशत (एनएसडीसी २०१२)

Country/ State	Total population in Millions	Total migrants in Millions	% of migrants to total population
India	1028.6	314.5	30.6
Jammu and Kashmir	10.1	1.8	17.8
Himachal Pradesh	6.1	2.2	36.1
Uttarakhand	8.5	3.1	36.2
Sikkim	0.54	0.19	34.6

जम्मू–कश्मीर को छोड़कर, भारत के हिमालयी राज्यों में कुल आबादी के लिए प्रवासियों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

संदर्भ

1. एटकिंसन एच (१८८२) – उत्तरी पश्चिमी प्रांत राजपत्र वॉल्यूम XII, हिमालयी राजपत्र।
2. जनगणना (२०११) – उत्तराखंड, जनगणना २०११, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत नई दिल्ली।
3. गोंजालेज एन (१९६१) - प्रवासी मजदूरी श्रमिक के पांच प्रकार के पारिवारिक संगठन, अमेरिकी मानवविज्ञानी, ६३ (६) पृष्ठ सं १२६४–१२८०.
4. ली ई (१९६६) – प्रवासन का एक सिद्धांत, जनसांख्यिकी ३(१), पृष्ठ सं ४७ –५७.
5. ममगाईं, आरपी (२००४) उत्तरांचल की पहाड़ी अर्थव्यवस्था में रोजगार, पलायन और आजीविका, पीएचडी शोध प्रबंध, क्षेत्रीय विकास का अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
6. ममगाईं और रेड्डी (२०१५) उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन, परिमाण, चुनौतियां और नीति विकल्प, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, हैदराबाद।
7. मैकलेमन (२०१७) पलायन और भूमि गिरावटः नए अनुभव और भविष्य के रुझान, वैश्विक भूमि दृष्टिकोण के कार्यकारी, दस्तावेज, यूएनसीसीडी।
8. एनएसडीसी (२०१०) – उत्तराखंड राज्य के लिए जिलावार कौशल अंतर अध्ययन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. एनएसएसओ (२०१०) – भारत २००७–२००८ में पलायन , सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) का राष्ट्रीय पतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), भारत सरकार।
10. रजी एस (२०१४) - कुरुक्षेत्र – ग्रामीण विकास की पत्रिका, सितंबर, २०१४, ६१ (११).

11. श्रीवास्तव आर (२०११) – भारत में आंतरिक प्रवासः इसकी विशेषताओं, प्रवृत्तियों और नीति चुनौतियों का एक सिंहावलोकन; यूनेस्को–यूनिसेफ की भारत में आंतरिक पलायन एवं मानव विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रस्तुत दस्तावेज, दिसंबर २०११, नई दिल्ली।

12. यूनेस्को (२०१३) – भारत में आंतरिक प्रवासियों के सामाजिक समावेश, यूनेस्को, नई दिल्ली।

13. संयुक्त राष्ट्र – डीईएसए (२०१५) – संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, जनसंख्या प्रभाग।

14. वाल्टन एच जी (१९१०) – ब्रिटिश गढ़वालः एक राजपत्रक, पुनर्मुद्रण १९९४, सिंधु प्रकाशन कंपनी, नई दिल्ली।

ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग

पलायन की स्थिति पर अंतरिम रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश (अप्रैल २०१८)

प्रतिवेदन की व्यापकता

वर्तमान प्रतिवेदन की व्यापकता इस प्रकार है:

1. राज्य में पलायन और संबंधित सामाजिक–आर्थिक स्थिति की वस्तु–स्थिति पर मौजूदा जानकारी का संक्षिप्त अवलोकन करना।
2. जिला और खंड के अनुसार गांवों से पलायन के कारणों और आयाम का सारांश तथा प्रवासियों के गंतव्य की जानकारी मुहैया करना।
3. जिन गांवों की जनसंख्या घट रही है और वहां बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, निर्जन गांवों/बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का जिला और खंडवार सारांश तैयार करना।
4. उन गांवों/बस्तियों का जिला और खंडवार सारिणी बनाना जहाँ परिवार बाहर के क्षेत्रों से आकर बस गए हैं।

प्रतिफल

I - मुख्य व्यवसाय

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है; कि राज्य के विभिन्न गांवों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है; इसके बाद श्रम और सरकारी सेवा है। ग्राम पंचायत स्तर से प्राप्त आंकड़े, जिला और राज्य औसत; नीचे दी गई सारणी में प्रस्तुत किये गए हैः

Table 4.1.1: ग्राम पंचायत स्तर का मुख्य व्यवसाय (जिला औसत)

जनपद का नाम	ग्राम पंचायतों का मुख्य व्यवसाय (लगभग प्रतिशत में)						
	मजदूरी	कृषि	उद्यान	डेरी	सरकारी सेवा	अन्य कार्य	**Total**
Uttarkashi	22.56	55.32	6.23	0.99	9.40	5.50	100.00
Chamoli	28.85	47.24	0.62	1.40	16.22	5.68	100.00
Rudraprayag	31.43	43.26	0.73	0.57	15.19	8.81	100.00
Tehri Garhwal	30.32	50.04	0.82	1.47	7.83	9.52	100.00
Dehradun	28.14	45.48	2.93	2.22	9.56	11.68	100.00
Pauri Garhwal	38.67	38.81	0.92	1.06	12.75	7.78	100.00
Pithoragarh	27.17	40.78	2.16	4.44	15.13	10.31	100.00
Bageswar	29.70	42.55	1.52	1.79	14.35	10.09	100.00

Almora	34.13	39.35	1.51	3.66	10.86	10.50	100.00
Champawat	34.23	42.41	2.29	7.22	6.48	7.37	100.00
Nainital	26.27	44.41	8.41	6.44	8.70	5.76	100.00
Udhamsingh Nagar	45.61	37.64	1.23	2.95	3.67	8.89	100.00
Haridwar	42.01	42.98	1.26	2.65	3.28	7.81	100.00

Table 4.1.2: ग्राम पंचायत स्तर का मुख्य व्यवसाय (राज्य औसत)							
State Name	ग्राम पंचायतों का मुख्य व्यवसाय (लगभग प्रतिशत में)						
	मजदूरी	कृषि	उद्यान	डेरी	सरकारी सेवा	अन्य कार्य	**Total**
Uttarakhand	32.22	43.59	2.11	2.64	10.82	8.63	100.00

II - अर्द्ध स्थायी और स्थायी प्रवासी

इस खंड में, अर्द्ध स्थायी और स्थायी प्रवासियों की जानकारी का विश्लेषण किया गया है। पिछले १० वर्षों में, ६३३८ ग्राम पंचायतों में कुल ३,८३,७२६ व्यक्ति अर्ध–स्थायी आधार पर प्रवासित हुए हैं; हालांकि वे समय–समय पर गांवों में अपने घर आते हैं; और स्थायी रूप से स्थानांतरित नहीं हुए हैं। पिछले १० वर्षों में, ३६४६ ग्राम पंचायतों से १,१८,६८१ स्थायी प्रवासी हैं। आंकड़े दर्शाते है कि राज्य के सभी जिलों में स्थायी प्रवासियों की तुलना में अधिक अर्द्ध स्थायी प्रवासियों की संख्या हैं।

Table 4.2.2: District wise migrants in last 10 years from gram panchayats				
जनपद का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या (जिन्होने पूर्ण रूपेण पलायन न किया हो/ घर में आना–जाना लगा रहता हो/अस्थाई रूप से रोजगार के लिए बाहर रहता हो)	पिछले 10 वर्षो में पलायन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (जिन्होने पूर्ण रूपेण पलायन न किया हो/ घर में आना–जाना लगा रहता हो/अस्थाई रूप से रोजगार के लिए बाहर रहता हो:	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो या अपनी जमीन बेच चुके हो/अथवा भूमि बंजर पड़ी हो/घरों पर ताले लगे हो/तथा बहुत कम गॉव आना होता हो)	पिछले 10 वर्षो में पूर्ण पलायन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो या अपनी जमीन बेच चुके हो/अथवा भूमि बंजर पड़ी हो/घरों पर ताले लगे हो/तथा बहुत कम गॉव आना होता हो):
Uttarkashi	376	19,893	111	2,727
Chamoli	556	32,020	373	14,289
Rudraprayag	316	22,735	230	7,835
Tehri Garhwal	934	71,509	585	18,830
Dehradun	231	25,781	53	2,802
Pauri Garhwal	1,025	47,488	821	25,584
Pithoragarh	589	31,786	384	9,883
Bageswar	346	23,388	195	5,912
Almora	1,022	53,611	646	16,207
Champawat	304	20,332	208	7,886
Nainital	339	20,951	213	4,823

Table 4.2.2: District wise migrants in last 10 years from gram panchayats				
जनपद का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या (जिन्होने पूर्ण रूपेण पलायन न किया हो/ घर में आना–जाना लगा रहता हो/अस्थाई रूप से रोजगार के लिए बाहर रहता हो)	पिछले 10 वर्षो में पलायन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (जिन्होने पूर्ण रूपेण पलायन न किया हो/ घर में आना–जाना लगा रहता हो/अस्थाई रूप से रोजगार के लिए बाहर रहता हो:	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो या अपनी जमीन बेच चुके हो/अथवा भूमि बंजर पड़ी हो/घरों पर ताले लगे हो/तथा बहुत कम गॉव आना होता हो)	पिछले 10 वर्षो में पूर्ण पलायन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो या अपनी जमीन बेच चुके हो/अथवा भूमि बंजर पड़ी हो/घरों पर ताले लगे हो/तथा बहुत कम गॉव आना होता हो):
Udhamsingh Nagar	147	6,064	54	952
Haridwar	153	8,168	73	1,251
Total	**6,338**	**383,726**	**3,946**	**118,981**

Table 4.2.3: State wise migrants in last 10 years from gram panchayats				
State Name	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या (जिन्होने पूर्ण रूपेण पलायन न किया हो/ घर में आना–जाना लगा रहता हो/अस्थाई रूप से रोजगार के लिए बाहर रहता हो)	पिछले 10 वर्षो में पलायन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (जिन्होने पूर्ण रूपेण पलायन न किया हो/ घर में आना–जाना लगा रहता हो/अस्थाई रूप से रोजगार के लिए बाहर रहता हो:	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो या अपनी जमीन बेच चुके हो/अथवा भूमि बंजर पड़ी हो/घरों पर ताले लगे हो/तथा बहुत कम गॉव आना होता हो)	पिछले 10 वर्षो में पूर्ण पलायन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो या अपनी जमीन बेच चुके हो/अथवा भूमि बंजर पड़ी हो/घरों पर ताले लगे हो/तथा बहुत कम गॉव आना होता हो):
Uttarakhand	6,338	383,726	3,946	118,981

III - पलायन के मुख्य कारण

पलायन का मुख्य कारण आजीविका/रोजगार; शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओ की कमी की समस्या है। नीचे दी गई सारणियो में विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किये गए है।

Table 4.3.2: District wise main reasons for migration from gram panchayats									Total
जनपद का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन के कारण (लगभग प्रतिशत में)								
	आजीविका / रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	शिक्षा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	इन्फ्राटक्चर (सड़क, बिजली, पानी व अन्य का आभाव) (प्रतिशत)	कृषि भूमी में उत्पादकता/ पैदावार की कमी (प्रतिशत)	परिवार/सगे संम्बन्धियों की देखा–देखी पलायन करना (प्रतिशत)	जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने करने के कारण (प्रतिशत)	अन्य कोई विशेष कारण (प्रतिशत)	
Uttarkashi	41.77	6.04	17.44	2.29	7.14	2.10	4.04	19.17	100.00

Chamoli	49.30	10.83	19.73	4.93	4.73	2.51	3.09	4.87	100.00
Rudraprayag	52.90	8.64	15.67	4.43	4.27	3.26	5.11	5.72	100.00
Tehri Garhwal	52.43	7.84	18.24	3.07	6.17	2.47	4.26	5.52	100.00
Dehradun	56.13	6.33	12.50	1.20	2.08	1.40	1.65	18.70	100.00
Pauri Garhwal	52.58	11.26	15.78	3.03	5.35	2.53	6.27	3.21	100.00
Pithoragarh	42.81	10.13	19.52	4.97	4.66	2.36	4.08	11.48	100.00
Bageswar	41.39	9.09	14.49	4.32	2.18	1.45	3.42	23.65	100.00
Almora	47.78	8.61	11.75	3.81	8.37	2.68	10.99	6.02	100.00
Champawat	54.90	6.67	10.24	5.46	6.31	4.30	6.65	5.46	100.00
Nainital	53.70	7.79	10.37	4.96	4.94	2.10	6.38	9.76	100.00
Udhamsingh Nagar	65.63	4.27	3.52	0.60	0.38	5.40	2.60	17.60	100.00
Haridwar	76.60	1.62	2.73	0.05	0.64	1.69	0.82	15.85	100.00

Table 4.3.3: State wise main reasons for migration from gram panchayats									
State Name	ग्राम पंचायत से पलायन के कारण (लगभग प्रतिशत में)								**Total**
	आजीविका / रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	शिक्षा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	इन्फ्राटक्चर (सड़क, बिजली, पानी व अन्य का आभाव) (प्रतिशत)	कृषि भूमी में उत्पादकता / पैदावार की कमी (प्रतिशत)	परिवार / सगे संम्बन्धियों की देखा–देखी पलायन करना (प्रतिशत)	जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने करने के कारण (प्रतिशत)	अन्य कोई विशेष कारण (प्रतिशत)	
Uttarakhand	50.16	8.83	15.21	3.74	5.44	2.52	5.61	8.48	100.00

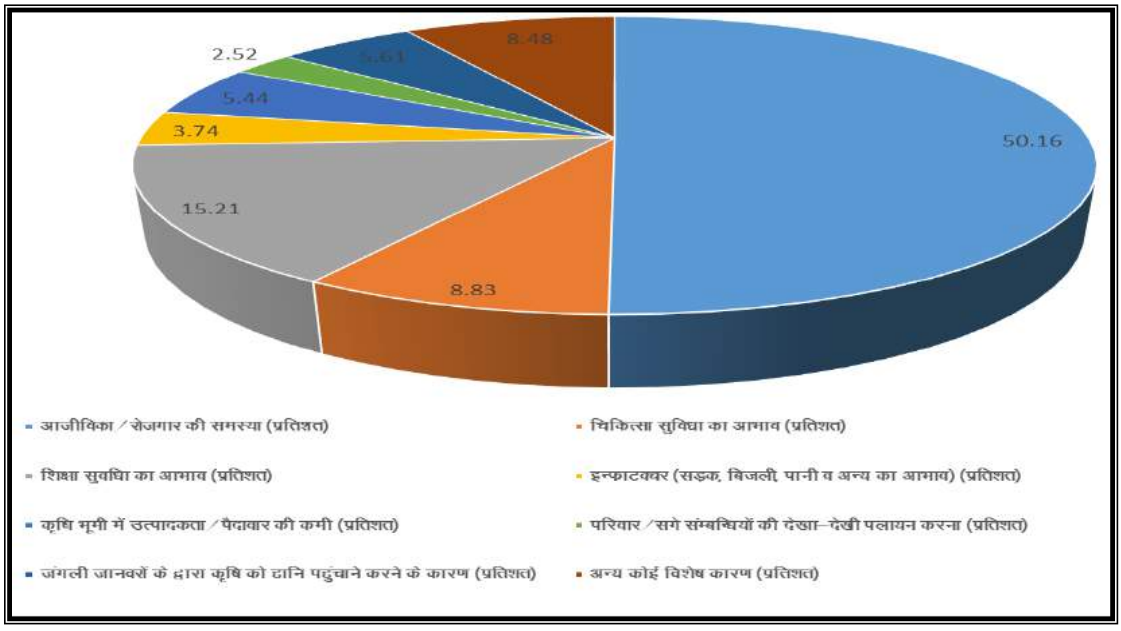

IV - प्रवासियों की उम्र

यह खंड ग्राम पंचायतों से प्रवासियों की उम्र का विश्लेषण करता है। प्रवासियों में ४२% से अधिक २६ से ३५ वर्ष की आयु के बीच हैं। विभिन्न ब्लॉक और जिलों की विस्तृत जानकारी नीचे सारणियो में दी गई है:

Table 4.4.2: District and Age wise Migration Status from gram panchayats				Total
जनपद का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन करने वालों की आयु (लगभग प्रतिशत में)			
	25 साल से कम आयु वर्ग (वर्तमान में)	26 से 35 आयु वर्ग (वर्तमान में)	35 साल से अधिक आयु वर्ग (वर्तमान में)	
Uttarkashi	30.68	36.56	32.77	100.00
Chamoli	26.71	43.49	29.79	100.00
Rudraprayag	28.97	41.83	29.20	100.00
Tehri Garhwal	29.26	40.92	29.82	100.00
Dehradun	38.41	34.47	27.12	100.00
Pauri Garhwal	29.23	41.67	29.10	100.00
Pithoragarh	28.32	42.58	29.10	100.00
Bageswar	33.92	42.10	23.97	100.00
Almora	29.19	42.22	28.59	100.00
Champawat	25.23	45.49	29.29	100.00
Nainital	29.48	44.57	25.96	100.00
Udhamsingh Nagar	16.66	43.34	40.00	100.00
Haridwar	13.99	52.79	33.22	100.00

Table 4.4.3: State and Age wise Migration Status from gram panchayats					Total
State Code	State Name	ग्राम पंचायत से पलायन करने वालों की आयु (लगभग प्रतिशत में)			
		25 साल से कम आयु वर्ग (वर्तमान में)	26 से 35 आयु वर्ग (वर्तमान में)	35 साल से अधिक आयु वर्ग (वर्तमान में)	
	Uttarakhand	28.66	42.25	29.09	100.00

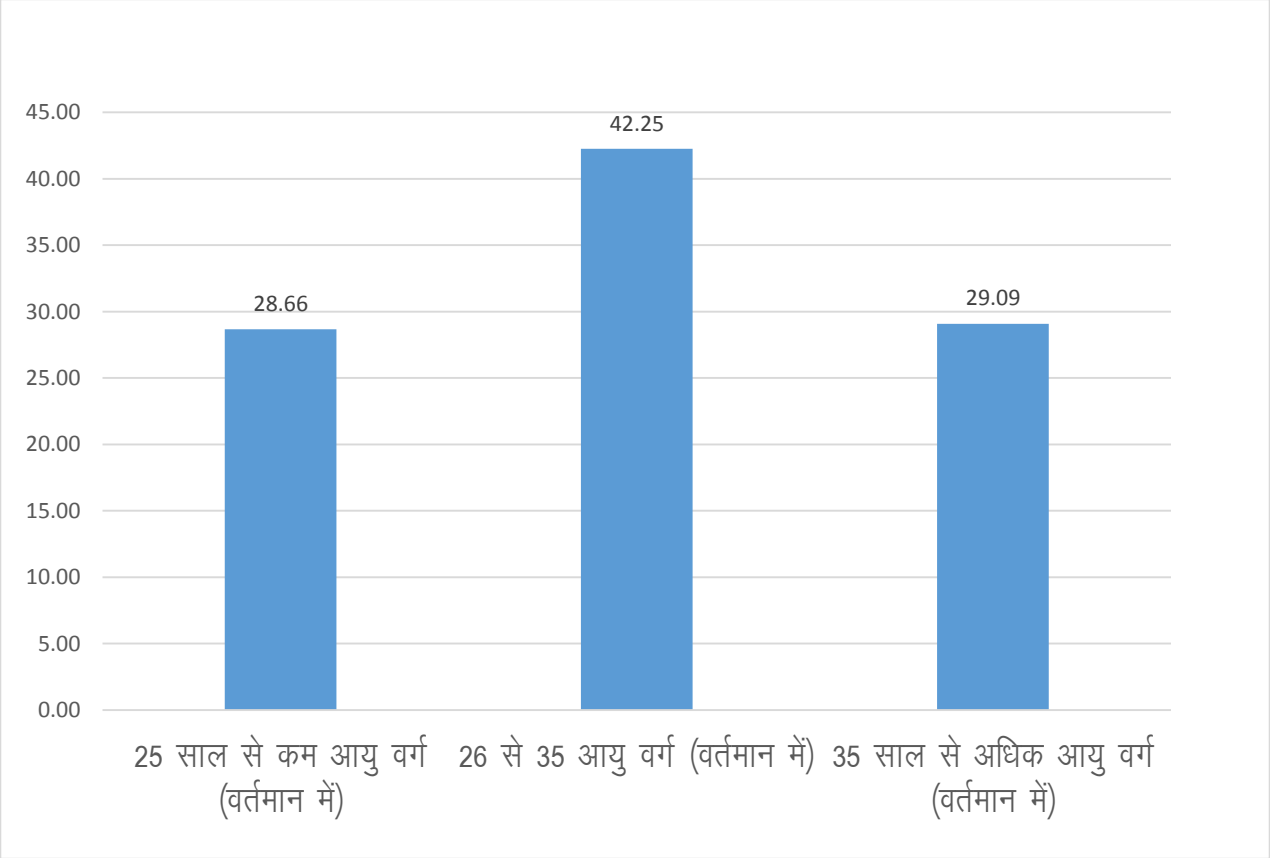

V - प्रवासियों का गंतव्य

यह खंड ग्राम पंचायतों से प्रवासियों के गंतव्य के विश्लेषण के परिणाम प्रस्तुत करता है। लगभग ३५% प्रवासी राज्य के अन्य जिलों में चले गए हैं जबकि २८% राज्य से बाहर प्रवास कर चुके हैं।

Table 4.5.2: District wise destination of migrants from Gram Panchayats						**Total**
जनपद का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन कहाँ किया गया (लगभग प्रतिशत में)					
	नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर	देश से बाहर	
Uttarkashi	39.14	20.27	22.37	17.34	0.89	100.00
Chamoli	19.79	13.34	50.48	15.88	0.51	100.00
Rudraprayag	19.34	12.66	40.51	25.69	1.80	100.00
Tehri Garhwal	17.73	9.42	40.78	28.98	3.09	100.00
Dehradun	57.12	23.67	8.08	10.46	0.67	100.00
Pauri Garhwal	19.61	9.55	36.15	34.15	0.54	100.00
Pithoragarh	15.70	33.07	34.33	16.67	0.23	100.00
Bageswar	15.45	22.00	37.19	25.18	0.19	100.00
Almora	7.13	13.00	32.37	47.08	0.43	100.00
Champawat	14.00	16.86	36.24	32.59	0.30	100.00
Nainital	35.49	17.93	21.47	24.64	0.47	100.00
Udhamsingh	27.48	8.48	28.04	31.11	4.89	100.00

Nagar						
Haridwar	44.27	18.29	16.10	20.85	0.49	100.00

Table 4.5.3: State wise destination of migrants from Gram Panchayats						Total
State Name	ग्राम पंचायत से पलायन कहॉ किया गया (लगभग प्रतिशत में)					
	नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर	देश से बाहर	
Uttarakhand	19.46	15.18	35.69	28.72	0.96	100

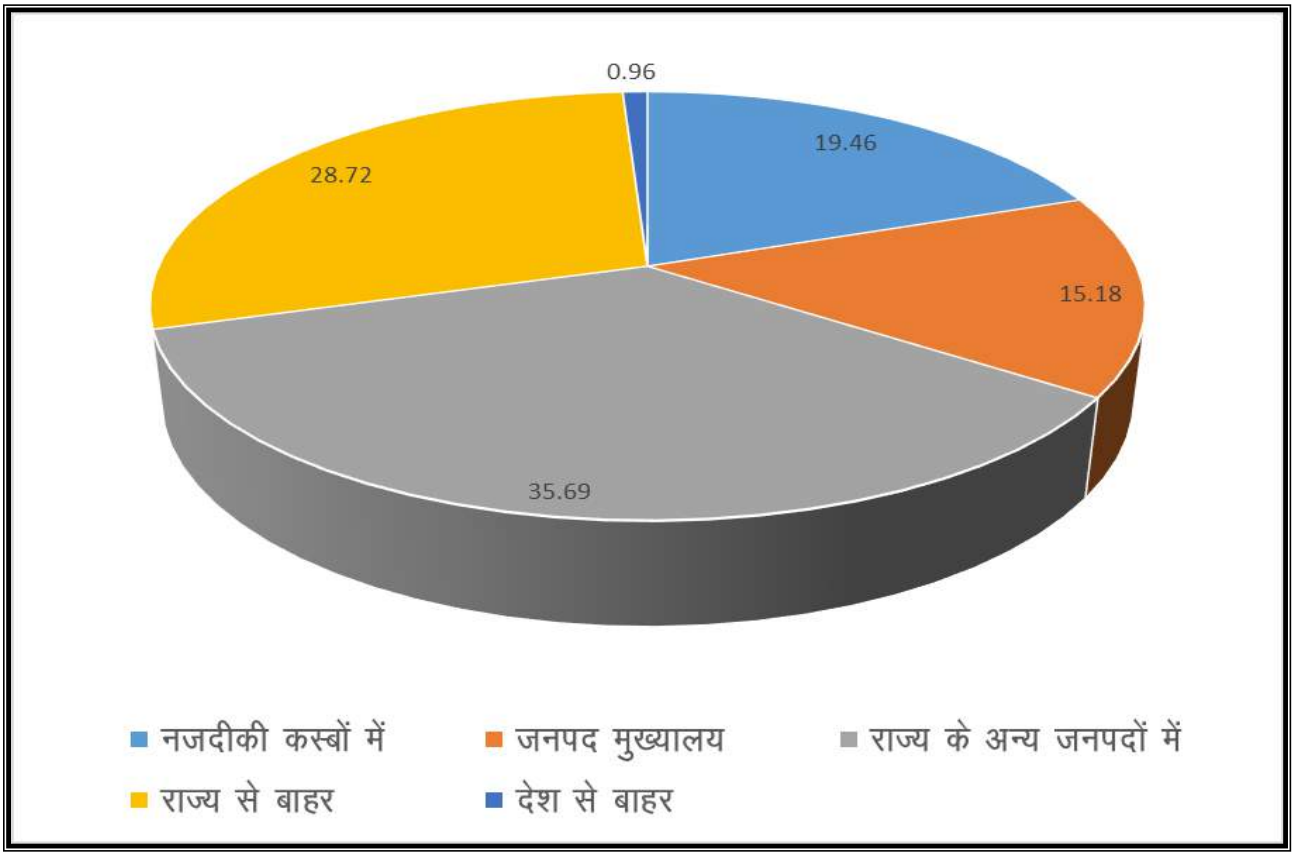

VI - २०११ के बाद पलायन से निर्जन गांवों की स्थिति

यह खंड जिला और विकास खंडवार राजस्व गांवों/तोक/मजरा की संख्या के सारांश का विवरण प्रस्तुत करता है जो २०११ के जनगणना के बाद निर्जन हुए है; ऐसे गांवों/तोक/मजरा की संख्या जो सड़कों से जुड़े नहीं है; जहां बिजली उपलब्ध नहीं है; पीने का पानी एक किमी के भीतर नहीं है; सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) उपलब्ध नहीं है और ऐसे गांवों की संख्या जिनकी हवाई दूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा से ०५ किमी के भीतर है।

Table 4.6.1.1: जिला और खंडवार ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वासित राजस्व गांवों/तोक/मजरा की संख्या (२०११ के बाद निर्जन)

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम/तोक/मजरा
Uttarkashi	Bhatwari	9
Uttarkashi	Chinalisaur	6
Uttarkashi	Dunda	11
Uttarkashi	Mori	18
Uttarkashi	Naugaon	26
Chamoli	Dasoli	7
Chamoli	Deval	7
Chamoli	Gairsan	6
Chamoli	Joshimath	4
Chamoli	Karnprayag	9
Chamoli	Narayanbagad	1
Chamoli	Pokhri	5
Chamoli	Tharali	2
Rudraprayag	Agastyamuni	6
Rudraprayag	Jakholi	9
Rudraprayag	Ukhimath	5
Tehri Garhwal	Bhilangna	4
Tehri Garhwal	Chamba	14
Tehri Garhwal	Deoprayag	10
Tehri Garhwal	Jakhnidhar	1
Tehri Garhwal	Jaunpur	12
Tehri Garhwal	Kirtinagar	2
Tehri Garhwal	Narendranagar	3
Tehri Garhwal	Thauldhar	12
Dehradun	Doiwala	1
Dehradun	Kalsi	1
Dehradun	Raipur	2
Dehradun	Shaspur	2
Dehradun	Vikasnagar	1
Pauri Garhwal	Berokhal	16
Pauri Garhwal	Dugadda	12
Pauri Garhwal	Dwarikhal	9
Pauri Garhwal	Ekeshwar	6
Pauri Garhwal	Kaljikhaal	12
Pauri Garhwal	Khirsu	8
Pauri Garhwal	Kot	28
Pauri Garhwal	Nainidanda	5
Pauri Garhwal	Pabau	7

Table 4.6.1.1: जिला और खंडवार ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वासित राजस्व गांवों/तोक/मजरा की संख्या (२०११ के बाद निर्जन)

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम/तोक/मजरा
Pauri Garhwal	Pauri	27
Pauri Garhwal	Pokhra	9
Pauri Garhwal	Rikhnikhaal	29
Pauri Garhwal	Thalisain	8
Pauri Garhwal	Yamkeshwar	8
Pauri Garhwal	Zahrikhal	2
Pithoragarh	Berinag	1
Pithoragarh	Dharchula	3
Pithoragarh	Gangolihat	55
Pithoragarh	Kanalichina	2
Pithoragarh	Munakot	5
Pithoragarh	Munsyari	6
Pithoragarh	Pithoragarh (Vin)	3
Bageswar	Bageswar	23
Bageswar	Garur	35
Bageswar	kapkot	19
Almora	Bhikiyasain	6
Almora	Chaukhutiya	6
Almora	Dhauladevi	7
Almora	Dwarahat	4
Almora	Hawalbagh	4
Almora	Lamgara	4
Almora	Sult	20
Almora	Syalde	2
Almora	Takula	2
Almora	Tadikhet	2
Champawat	Baarakot	3
Champawat	Champawat	35
Champawat	Lohaghat	15
Champawat	paati	11
Nainital	Betalghat	3
Nainital	Bhimtal	3
Nainital	Dhari	2
Nainital	Haldwani	2
Nainital	Kotabag	1
Nainital	Okhalkanda	9
Nainital	Ramgarh	1
Nainital	Ramnagar	1

Table 4.6.1.1: जिला और खंडवार ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वासित राजस्व गांवों/तोक/मजरा की संख्या (२०११ के बाद निर्जन)		
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम/तोक/मजरा
Udhamsingh Nagar	Gadarpur	5
Udhamsingh Nagar	Jaspur	6
Udhamsingh Nagar	Kashipur	4
Udhamsingh Nagar	Rudrapur	3
Udhamsingh Nagar	Sitarganj	1
Haridwar	Bhadrabad	3
Haridwar	Bhagwanpur	1
Haridwar	Khanpur	7
Haridwar	Laksar	7
Haridwar	Narsan	11
Haridwar	Roorkee	9
	Total	**734**

Table 4.6.1.2: District wise Number of uninhabited revenue villages/toks/majra at Gram Panchayat Level (De-populated After 2011)	
जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम ग्राम/तोक/मजरा
Uttarkashi	70
Chamoli	41
Rudraprayag	20
Tehri Garhwal	58
Dehradun	7
Pauri Garhwal	186
Pithoragarh	75
Bageswar	77
Almora	57
Champawat	64
Nainital	22
Udhamsingh Nagar	19
Haridwar	38
Total (state)	**734**

Table 4.6.6.2: District wise Number of uninhabited revenue villages/toks/majra at Gram Panchayat Level (within 5 Km from International Border)	
जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम/तोक/मजरा
Chamoli	1
Pithoragarh	8

Champawat	5
Total(state)	**14**

VII - कुल ऐसे गांव जहाँ पिछले १० वर्षों में अन्य गांवों/शहर/कस्बों से पलायन कर उस गाँव में आकर बसे होः

यह खंड, जिले और खंडवार ऐसे गाँव की संख्या; जहाँ पिछले १० वर्षों में अन्य गांवों/शहर/कस्बों से पलायन कर उस गाँव में आकर बसे हो का ब्योरा प्रस्तुत करता हैं।

Table 4.7.2: District wise Number of villages where people have in-migrated and settled in last 10 years from other villages/ towns or small towns	
जनपद का नाम	कुल ऐसे गॉव जहॉ पिछले 10 वर्षो में अन्य गॉव/शहर/कस्बों से पलायन कर उस गॉव में आकर बसे होः
Uttarkashi	16
Chamoli	26
Rudraprayag	28
Tehri Garhwal	76
Dehradun	114
Pauri Garhwal	46
Pithoragarh	69
Bageswar	24
Almora	39
Champawat	60
Nainital	139
Udhamsingh Nagar	92
Haridwar	121
Total (State)	**850**

VIII - राजस्व गांवों/तोक जहाँ जनसंख्या वर्ष २०११ के बाद ५०% कम हुई हैः

यह खंड जिला और विकास खंडवार राजस्व गांवों/तोक/मजरा की संख्या के सारांश का विवरण प्रस्तुत करता है जिनमे २०११ के जनगणना के बाद जनसँख्या ५०% कम हुई है; ऐसे गांवों की संख्या जो सड़कों से जुड़े नहीं है; जहां बिजली उपलब्ध नहीं है; पीने का पानी एक किमी के भीतर नहीं है; सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) उपलब्ध नहीं है और ऐसे गांवों की संख्या जिनकी हवाई दूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा से ०५ किमी के भीतर है।

Table 4.8.1.2: District wise Number of revenue villages/toks/majra at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011)	
जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम/तोक/मजरा
Uttarkashi	63
Chamoli	18
Rudraprayag	23

Tehri Garhwal	71
Dehradun	42
Pauri Garhwal	112
Pithoragarh	45
Bageswar	37
Almora	80
Champawat	44
Nainital	14
Udhamsingh Nagar	9
Haridwar	7
Total (state)	**565**

Table 4.8.6.2: District wise Number of revenue villages/toks/majra at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011) (within 5 Km from International Border)

जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम/तोक/मजरा
Pithoragarh	2
Champawat	4
Total (State)	**6**